भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या –2394

शुक्रवार, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 (शक)

कार्मिकों की संख्या में भारी अंतर

2394. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार व्यय बजट और रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के बीच केन्द्र सरकार के कार्मिकों की संख्या के आंकड़ों में भारी अंतर है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अंतरों के कारण का विश्लेषण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्मिकों की संख्या के आंकड़े समरूप हैं और सरकार के व्यय बजट के विनियमन के लिए पर्याप्त योजना हो, क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) से (ग): 7वें वेतन आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आंकड़ों में अंतर, विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपनाए गए मापदण्डों में अंतर के कारण है। व्यय बजट के लिए संकलित आंकड़े, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्थापना की अनुमानित संख्या के बारे में सूचना पर आधारित हैं। इस प्रकार संकलित सूचना, सरकारी संस्थापनाओं और अनुदानग्राही संस्थाओं/निकायों के संबंध में है और इसमें दैनिक मजदूरी पर रखे गए अनियत मजदूर शामिल नहीं हैं। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की गणना" से संबंधित रिपोर्ट का प्रकाशन, मंत्रालयों और विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालयों से अपर्याप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए 2011 से बंद कर दिया गया है।

*****